



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

H.O.  
8/11/99

सं. 279 ]  
No. 279]

नई दिल्ली, मंगलबार, जून 8, 1999/ज्येष्ठ 18, 1921  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 1999/JYAISTHA 18, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1999

सं. 35/99-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा. का. नि. 415 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) संशोधन नियम, 1999 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमाशुल्क विशेषाधिकार विनियमन) नियम, 1957 में,—

(i) नियम 4क में,—

(क) उपनियम (2) के खण्ड (ग) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि उस दशा में जहां ऐसी आमा कम्पनी भी ऐसे मोटर यान के विक्रय के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करती है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अनुज्ञा से मोटर यान को मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन या स्क्रैपिंग के लिए किसी उपयुक्त व्ययन अभिकरण को विक्री किया जा सकेगा।”

(ख) उपनियम (2) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी मोटरयान का, जिसकी ईंजन क्षमता 1500 सी सी से अधिक नहीं है, विदेश मंत्रालय के माध्यम से और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अनुज्ञा से, समुचित सीमाशुल्क का संदाय पर, उस तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर जिसको ऐसे मोटरयान का आयात किया गया था, किसी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकेगा।”

(ग) उपनियम (3) में, खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ii) उपनियम (2) में खण्ड (क) के अधीन स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन को किसी मोटरयान के विक्रय या अन्यथा व्यवहार के लिए प्रत्येक आवेदन, विदेश मंत्रालय को परिशिष्ट-1 के प्रूरुप में किया जाएगा और दुर्घटना से ग्रस्त या पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मोटरयान की दशा में विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को आवेदन भेजेगा यदि स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन और बीमा कम्पनी ने इस प्रकार किए गए प्रस्ताव से इंकार कर दिया है या स्टेट ट्रैडिंग कार्पोरेशन और बीमा कम्पनी का प्रस्ताव विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है।"

(घ) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) कोई विशेष प्रयोजन यान जैसे संचार यान या बखारबंद यान के बल—

(क) अन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को विक्रीत किया जा सकेगा, या

(ख) पुनः निर्यात किया जा सकेगा, या

(ग) स्क्रेपिंग के लिए निकटतम सीमाशुल्क-सदन को या स्क्रेपिंग के लिए किसी उपयुक्त भारतीय अभिकरण को प्राधिकृत करने के लिए अध्यर्थित किया जा सकेगा और इस प्रकार अभिप्राप्त स्क्रैप के विक्रय आगम की, यदि कोई हों, ऐसे यान के लिए उद्यग्रहणीय शुल्क की कटौती करने के पश्चात् विशेषाधिकार व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाएगी;"

(ii) नियम 5 में,—

(क) उपनियम (1) में, "वसूल किए जाने वाले शुल्क" शब्दों से आरम्भ होकर "और निर्धारित की जाएगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वसूल किए जाने वाले शुल्क भारत में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के मुख्यालय के निकटतम सीमाशुल्क आयुक्त के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा";

(ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) कोई मोटरयान का जिसकी इंजन क्षमता 1500 सीसी या उससे कम हो, उसके आवाह करने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर किसी गैर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को विक्रीत या अन्यथा व्यवहार किया जा सकेगा।

(1ख) उपनियम (1क) के अधीन विक्रीत या अन्यथा व्यवहार कियी यान पर सीमाशुल्क का संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के भारत में मुख्यालय के निकटतम सीमाशुल्क आयुक्त को किया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त यान के मामले के सिवाय ऐसे मोटरयान के लिए वसूल किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण अवक्षयित मूल्य पर किया जाएगा जो, बरते हुए मोटर यान के आवाह की दशा में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मापमान के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबन्ध करने के पश्चात् आया हो। ऐसे यान पर शुल्क की दर और विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करने के लिए विनियमन दर नियम 4क के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन उक्त बोर्ड द्वारा ऐसे विक्रय या अन्यथा व्यवहार के अनुमोदन की तारीख को यथा लागू मानी जाएगी।

(1ग) उप-नियम (1ख) में निर्दिष्ट किसी दुर्घटनाग्रस्त या पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त यान की दशा में मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा और सीमाशुल्क की दर वह मानी जाएगी जो ऐसे मोटरयान को लागू हो, यदि वह ऐसे विक्रय के समय इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त न हुआ होता।"

[फा. सं. 421/4/95-सी.शु. IV]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 4-सीमाशुल्क तारीख 8 जनवरी, 1957 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और उनका अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं. 34-सीमाशुल्क, तारीख 20 फरवरी, 1985 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 1999

**No. 35/99-CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 415 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157, read with sub-section (3) of section 160 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following rules to further amend the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Privileged Persons' (Regulations of Customs Privileges) Rules, 1957,—

(i) in rule 4A :—

(a) in sub-rule (2), in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in case such insurance company also declines to accept the offer for sale of such motor vehicle, the motor vehicle, with the permission of Central Board of Excise and Customs, may be sold to the Metal Scrap Trading Corporation or any suitable disposal agency for scrapping."

(b) In sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) may, notwithstanding any thing contained in clauses (a), (b) and (c), sell or otherwise dispose of any motor vehicle where the engine capacity thereof does not exceed 1500 CC, to any non-privileged person, with the permission of Central Board of Excise and Customs through the Ministry of External Affairs, on payment of appropriate custom duty, on expiry of three years from the date on which such motor vehicle was imported";

(c) In sub-rule (3), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Every application for sale or disposal otherwise of a motor vehicle to the State Trading Corporation, under clause (c) of sub-rule (2), shall be made to the Ministry of External Affairs, in the form in Appendix-VI and in case of accidented or totally damaged motor vehicle, the Ministry of External Affairs shall remit the application to the Central Board of Excise and Customs, if the State Trading Corporation and the insurance company have declined the offers so made or the offers of the State Trading Corporation and the insurance company are not acceptable to the Privileged Person.";

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Any special purpose vehicle such as communication vehicle or armoured vehicle may only be;

(a) sold to another privileged person; or

(b) re-exported, or

(c) surrendered to the nearest Custom House, for scrapping or authorising a suitable Indian agency for scrapping and the sale proceeds, of scrap so obtained, if any, shall be reimbursed to the privileged person after deducting the duty leviable for such vehicle;"

(ii) in rule 5,—

(a) in sub-rule (1), for the portion beginning with the words "the duty to be recovered shall" and ending with the words "the time of importation of the goods", the following shall be substituted, namely :—

"The duty to be recovered shall be assessed in consultation with the Commissioner of Customs nearest to the headquarter of the Privileged Person in India";

(b) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(1A) Any motor vehicle which has engine capacity of 1500 CC and below may also be sold or otherwise disposed of to a non-privileged person on expiry of three years from the date of its importation.

(1B) The Customs duty on any vehicle sold or otherwise disposed of under sub-rule (1A) shall be paid to the Commissioner of Customs nearest to the headquarters in India of the privileged person concerned. The duty to be recovered for such motor vehicle, except in case of accidented or totally damaged vehicle, shall be assessed on the depreciated value arrived after providing for depreciation at the scales specified by the Central Board of Excise and Customs in case of import of second hand motor vehicles. The rate of duty on such vehicle and the exchange rate for conversion of Foreign Currency into Indian Currency shall be taken as applicable on the date of approval of such sale or otherwise disposal by the said Board under clause (d) of sub-rule (2) of rule 4A..

(1C) In case of any accidented or totally damaged vehicle referred to in sub-rule (1B), the value shall be the transaction value and rate of custom duty shall be taken as that applicable to such motor vehicles, if it had not been so accidented or damaged at the time of such sale".

[F. No. 421/4/95-Cus. IV]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 4-CUS dated 8th January, 1957 and last amended by the notification number 34-CUS dated 20th February, 1985.